(11)	
	Note 3 : The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of applications. **Note 4 :** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendation has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the Commission. **Note 5 :** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendation has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation of Armed Forces Personnel Re-employed) consisting of :— 1. Secretary, Union Public Service Commission —Chairman 2. Additional Secretary Union Public Service Commission —Member 3. Joint Secretary (Examination)/Joint Secretary (Recruitment) Union Public Service Commission —Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary."

[F. No. 39021/10/2009-Estt. (B)]

RAKESH MOZA, Under Secy.

Foot Note : The principal rules were published in the Gazette of India *vide* number G.S.R. 2, dated 6th January, 2011.

नई दिल्ली, 7 मई, 2012

सा.का.नि. 110.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग संपदा प्रबंधक और मीटिंग अधिकारी भर्ती नियम, 2001 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग संपदा प्रबंधक और मीटिंग अधिकारी भर्ती (संशोधन) नियम, 2012 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. संघ लोक सेवा आयोग संपदा प्रबंधक और मीटिंग अधिकारी भर्ती नियम, 2001 में,—

(i) नियम 2 में "वेतनमान" शब्दों के स्थान पर "वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) नियम 3 में "स्तंभ 5 से स्तंभ 14" शब्दों और अंकों के स्थान पर "स्तंभ 5 से स्तंभ 13" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(iii) अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :—

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
संपदा प्रबंधक और मीटिंग अधिकारी	2* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2, 9300—34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
संयुक्त पद्धति प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ।)	I. प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :— केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत संगठनों में से ऐसे अधिकारी :— (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2; 9300—34800 रु.+ ग्रेड वेतन 4200 रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं अर्थात् :— (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल या यांत्रिक या विद्युत या स्वच्छता या लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी में डिप्लोमा या समतुल्य; और (ii) कार्यालय भवन के अनुरक्षण और रखरखाव में जिसके अंतर्गत स्वच्छता संबंधी स्थापन और वातानुकूलन उपस्कर या विद्युत संस्थापन भी है, पांच वर्ष का अनुभव ।

(11)	
	II. वेतन बैंड-2, 9300—34800 रु.+ ग्रेड वेतन 4200 रु. में ऐसे विभागीय संपदा पर्यवेक्षक जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है पर भी बाह्य व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा और यदि उस पद पर नियुक्ति के लिए उनका चयन हो जाता है तो वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा । **टिप्पण 1 :** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति, प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । **टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 3 :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी । **टिप्पण 4 :** प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा, जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित व विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।"

[फा. सं. 39021/9/2010-स्था. (बी)]

राकेश मोजा, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना सं. सा.का.नि. 152, तारीख 17 मार्च, 2001 द्वारा भारत के राजपत्र में भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे ।

New Delhi, the 7th May, 2012

G.S.R. 110.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Union Public Service Commission Estate Manager and Meeting Officer Recruitment Rules, 2001, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Union Public Service Commission Estate Manager and Meeting Officer Recruitment (Amendment) Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Union Public Service Commission Estate Manager and Meeting Officer Recruitment Rules, 2001,—

(i) in rule 2, for the words "scale of pay", the words "pay band and grade pay or pay scale" shall be substituted;

(ii) in rule 3, for the words and figures "columns 5 to 14", the words and figures "column 5 to 13" shall be substituted;

(iii) for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely :—

"SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Estate Manager and Meeting Officer	2* (2012) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-2, Rs.9300—34800 plus Grade Pay Rs. 4600	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made
(10)	(11)
By composite method Promotion/Deputation (including short term contract).	**I. Deputation (including short term contract) :—** From amongst officers in the Central Government or State Governments or Union territories or Universities or Recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Statutory or Autonomous Organisations:— (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay band-2, Rs. 9300—34800 with grade pay of Rs. 4200 or equivalent in the parent cadre or department; or (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:—

	(11)
	(i) Diploma in Civil or Mechanical or Electrical or Sanitary or Public Health Engineering from a recognised University or equivalent; and (ii) five years' experience in the upkeep and maintenance of office building, including sanitary installations and air conditioning equipment or electrical installations. II. The Departmental Estate Supervisor in Pay Band-2 Rs. 9300-34800 with Grade Pay of Rs. 4200 with five years of regular service in the grade shall also be considered along with outsiders and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion. **Note 1:** Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2 :** Period of deputation including period of deputation to another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organizations or departments of the Central Government shall not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. **Note 3 :** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendation has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the Commission. **Note 4 :** For the purpose of appointment on deputation or absorption basis the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendation has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission necessary."

[F. No. 39021/9/2010-Estt. (B)]
RAKESH MOZA, Under Secy.

Foot Note : The principal rules were published in the Gazette of India part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 152, dated 17th March, 2001.